साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 39 | प्रति सोमवार इंदौर, 29 अप्रैल से 4 मई 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

अगर पुनः मोदी तो उत्तरी व पूर्वोत्तर चीन को भेंट कर देगा, इसलिए चुनाव नहीं लड़े

चीन के मोटे फायदे के लिए 10 सालों में सफाई, कैशलेस, नोटबंदी जीएसटी, तालाबंदी

सेना को 40 लाख से घटा 10 लाख, 40 दिन के गोला बारूद को 10 दिन का व अग्निवीर सब चीन के सामने समर्पण के लिए

घोर धूर्त जाहिल मोदी उसकी भाजपा और आरएसएस की चीन परस्ती न केवल देश की जनता वरन अमेरिका रूस ब्रिटेन के साथ विश्व शैतान संघ आदि सभी भलीभांति परिचित हैं। अभी भी अमेरिका ब्रिटेन व अन्य देश चीन के भारतीय सीमाओं में अतिक्रमण निर्माण और घुसपैठ के बारे में लगातार उपग्रहों की सूचनाओं को साझा कर लगातार सूचित करने के बाद में भीमोदीने स्पष्ट कह दिया हमारी सीमाओं में कोई भी नही घुसा है और किसी ने भी अतिक्रमण नही किया है यह चीन की मोदी परस्ती का खुला उदाहरण न केवल देश की जनता उसकी अपनी बीजेपी आरएसएस के साथ विपक्षियों को देने के साथ अमेरिका ब्रिटेन रूस को बताने के साथ पूरी दुनिया को भी बता दिया है।

उसके कश्मीरी पंडितो के नरसंहार के बाद बाबरी मस्जिद से लौटते राम भक्तो के नरसंहार गोधरा किन्नर शहर के कारण अमेरिका ने उसका वीजा रद्द करके उसको घुसने से मना कर दिया था इसलिए उसने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठो को ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री बनने के साथ ही गुजरात के सारे उद्योग को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया और चार बार चीन जाकर वहां की कंपनियो को गुजरात में बसा कर गुजरात के सहस्त्रो वर्ष पुराने उद्योगो यथा साड़ियो, वस्त्रो, हीरा आदि रत्नो, टाइल्स फार्मा मशीनरी रसायन खिलौने आदि को नष्ट करने के लिए अपने मुख्यमंत्री काल में हजारो करोड़ रुपए का धन लेकर षड्यंत्र कर दिया था। जिस परना तो गुजरात की जनता नेऔर नही विपक्षियो ने कोई हो हल्ला मचाया इससे प्रेरित होकर उसने गेट की सत्ता पर उसी ब्लैकमेलिंग के दम पर केंद्र की सत्ता पर सारे अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओ लाल कृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा को पीछे धकेल कब्जा कर लिया। बाकी जो वरिष्ठ सदस्यो को जिन की छवि बहुत अच्छी थी पार्टी में लेना आवश्यक हो गया। जिसमे श्रीमती सुषमा स्वराज अरुण जेटली मोहन पर्रिकर, अनिल माधव दवे, आदि को उड़ाने चिकित्सीय हत्या करवाकर यमलोक भेज दिया। एकमात्र बचे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाकर खुलकर 12 से 15 लाख करोड़ का कबाड़ा समय बाधित पुराने विमान टैंक तोप मिसाइल हथियार मोटे कमीशन पर रूस अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन इजरायल आदि से खरीद विश्व में पांचवे नंबर का कबाड़ा हथियार का आयातक बन गया।

(शेष पेज 2 पर)

कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में मोदी समेत बीजेपी के दावों में है कितना दम

जबसे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है, भाजपा नेताओं की ओर से घोषणापत्र को लेकर तीखे हमले किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के मैनिफ़ेस्टो (चुनावी घोषणापत्र) का हवाला देकर कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. इस आर्टिकल में हम इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इन शीर्ष नेताओं के कांग्रेस मैनिफ़ेस्टो को लेकर किए गए दावों में कितनी सच्चाई है. लेकिन पहले जान लेते हैं कि इन नेताओं ने कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर क्या-क्या कहा है?

कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर बीजेपी के दावे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि, 'अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक नागरिक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा.' उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के संपत्ति के बंटवारे को लेकर दिए बयान का ज़िक्र छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में किया. छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज़्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी.' वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, 'कांग्रेस ने इस बार के मैनिफ़ेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक रैली में कहा कि 'कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे.'

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 'जब मैंने कांग्रेस के मैनिफ़ेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफ़ेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफ़ेस्टो है. जैसे मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की थी, वही आज कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है.'

कांग्रेस का जवाब

इन तमाम आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा, 'कांग्रेस के न्याय पत्र का लक्ष्य हर जाति और समुदाय के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हाशिए पर रह रहे लोगों को न्याय मुहैया करना है और आपको आपके सलाहकार उन बातों को लेकर गलत खबर दे रहे हैं जो घोषणापत्र में लिखी ही नहीं हैं.'

प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'कांग्रेस ने 55 साल में क्या किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था तब इंदिरा जी ने अपना मंगलसूत्र व गहने दान किए. लाखों महिलाओं ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र कुर्बान किए. जब मेरी बहनों को नोटबंदी में अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े, तब प्रधानमंत्री जी कहां थे?'

(शेष पेज 7 पर)

मोदी की जनता को लूटने व खोखला करने की खोटी नियत व बैंक कर्मियों का दुर्व्यवहार

जनता ने कम किया जमा कर रखना बैंकों में बचत

भारत मे सन् 2006 से ही आधार कार्ड बनाने, आवश्यक करने के कारण जनता का डाटा की पहले सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे थे बाइमेरछोटे-छोटे ठेके देकरउसके बाद में अपने खास लोगो को अधिकारियो ने अपने खास लोगों को ठेके देकर भी डाटा इकठ्ठा करके, बाद में गुजराती कंपनियो के ठेके पर काम कर रहे थे। बिकने व दुरूपयोग की शिकायत व शुरुआत हो चुकी थी। जिसका सबसे पहले सदुपयोग भाजपा के पार्षदो से लेकर विधायको सांसदो ने खुलकर सदुपयोग करने के साथ प्रदेश की सत्ता को 20 साल से और देश की सत्ता को 10 साल के कब्जे में रखा बार-बार कहने लिखने छापने व सर्वोच्च न्यायालय के अनेको निर्णय के बाद में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियो के साथ पर नाचने और कमीशन खाने वाली सरकार ने अभी तक अपना तो बहुत दूर अपने खासदेश के वित्तीय संस्थानो बैंको रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक के साथ सभी सरकारी निजी सहकारी बैंको के खातो के डाटा के साथ- साथ क्रेडिट डेबिट भीम यूपीआई पेटीएम एटीएम आदि विभिन्न लेन देन के डाटा को भी सुरक्षित नही किया जा सका जो आज डार्क नेट पर खुलाम बिकने के साथ-साथ हैकर्स लगातार उसमे डाक डालकर सेंध लग रहे हैं 2022-23 में 67 लाख खातो

कैशलेस, बैंकों का लेनदेन का सारा डाटा सरकार, चीनी अमेरिकी कंपनियां व हैकर्स के पास, साइबर क्राइम रोकने में असफल

में सेंध लगाई गई। बेशक इसमें स्टेट बैंक व अन्य बैंको का स्टाफ कही ना कही इस जलसा जिओ डकैती में अपनी भूमिका अदा कर मोटी कमाई कर रहा है परंतु सरकार पकड़ने में नाकामयाब होने के साथ-साथ देश की साइबर मुट्ठी भर निकम्मी भ्रष्ट जालसाज पुलिस भी हैकर्स की आधुनिक तकनीक के सामने असफल नजर आती है। यही कारण है, बैंको में छोटे व मध्यम वर्गी जमा कर्ताओं अपने बैंको से दूरी बनाना शुरू कर दियाफिर दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियो के रखले और कमिश्न खोर मोदी की खोटी नियत के साथ आरएसएस का 1930 से चल रहा जर्मन तानाशाह हिटलर का देश पर राज करने व सत्ता मे बने रहने के लिए की जनता को 95% गरीब बेरोजगार और भुखमरी अशिक्षा का शिकार बना गुलाम बनाकर रखना आवश्यक है। के कार्यक्रम पर चलती हुई और इस कार्यक्रम को पूरा करने मोदी ने आते ही साथ देश में सफाई के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा महानगरो की सड़को से लेकर नगरो की सड़को तक पद मारो और खेलो पर व्यवसाय करने वाले दो करोड़ से ज्यादा लोगो कोसफाई के नाम पर उजाड़ 10 करोड़ लोगो को भिखारी बना दिया। कहानी की शुरुआत मे सफाई के बाद उसने फिर कैशलेस का तांडव कर लोगों की आय व्यय, बचतो व लेन देन पर निगाह रखने का तांडव कर हर परिवार की घरेलू बचतो व छोटे व्यापारियो को आवश्यक रूप से बैंको की डकैती के मकड़ जाल मे उलझाया। (शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

भ्रष्ट जालसाज मंत्री पार्षद आयुक्त अधिकारी इंजीनियर कर्मचारी ठेकेदार सभी फर्जीवाड़े के हिस्सेदार

पेज 8 का शेष

उस समय सीपीडब्ल्यूडी का पूरे देश मे लागू होने वाला प्रदेश की पीडब्लूडी द्वारा जारी किया गया एसओआर के हिसाब सेडीपीआर बनाई गई कितने निविदा कर्ताओ ने निविदायें भरी। किसने किस दर की निविदाएं भरी थी उसका ठेकेदारी का किस कैटेगरी का लाइसेंस था। उसका अनुभव आदि के साथ जो निविदा भरी गई थी उसमे कितने अर्नेस्ट मनी की किस बैंक की कितने की एसडीआर लगाई गई? किसको कैसे किस दर का, पर कार्यादेश मिला वास्तविकता मे किसने कार्य किया? बेशक अधूरा छोड़ रहा हूं ताकि फ्रकार इसका सदुपयोग ना कर सके। सारी जानकारी अगर निकल जाए तो सारे के सारे पार्षद से लेकरप्रभारी जानकारी विभाग मंत्री ड्राफ्टमैन सब इंजीनियर से लेकर अधीक्षक व मुख्य अभियंता तक सहायक आयुक्त उपायुक्त महापौर और आयुक्त तक पर एफ आई आर करके सबको कोर्ट में खड़ा करने पर सब की नौकरियां चली जाएगी। मैं पिछले 15 साल से सूचना के अधिकार मे इन जालसाज भेड़ियो से जानकारी मांग रहा हूं? अपील भी लगा रहा हूं परंतु सारे डकैत भ्रष्टाचारी सूअर जिसमे नीचे से लेकर ऊपर तक सब लूट डकैती मे हिस्सेदार हैं। हरामखोरो ने कभी जानकारी नही दी। उल्टे सीधे जवाब के फ्त्र महीनो बाद जरूर दिए। कभी धारा 7(6) मे निशुल्क जानकारी नही दी गईबेशक पूरे नगर निगम मे सूचना के अधिकार मे उन्ही दलालो को जवाब दिए जाते हैं। जो वहीं के अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगवा कर अपने ही वरिष्ठो को उलझा कर मोटी लाखो मे वसूली कर लेते हैं।

जहां तक पुलिस का सवाल हैतो सारी फाइले सारे पत्र लेकरवह स्वयं हीनेताओ मंत्रियोंके सारे पर नाचती है ना तो वह ढंग से केसे का अध्ययन कर पाएंगे क्योंकि पुलिस को आईपीसी और सीआरपीसी के अतिरिक्त शासकीय निर्माण कार्य की प्रक्रिया की खातबही एमबी की निल बटे सन्नाटा जानकारी है। जबकि वहां विशेषज्ञ इंजीनियरो की आवश्यकता होती है।

मैं वर्षो से कह रहा हूं की सेवा निवृत्त लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय जल संसाधन गृह निर्माण आदि केइंजीनियरिंग कीतकनीकी अंकेक्षण समिति बनाई जानी चाहिए जो हर निर्माण कार्य के पूर्व प्रस्तावना डीपीआर की जानकारी ली और उसकी भौगोलिक वास्तविक वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे उसके बाद वह कार्य की मंजूरी दे। पूरी दुनिया के सभी देशो मे सभी प्रकार की इंजीनियरिंग के लिएतकनीकी अंकेक्षण विभाग होता हैवह पहले हर चीज का अध्ययन करता है उसके बाद मंजूरी देता है और बनते समय सतत निगरानी कर उसकी गुणवत्ता और आवश्यकता पर ध्यान देता हैपर भारत मे 75 साल की आजादी के बाद मे अभी तककिसी भी तकनीकी कार्य के लिए तकनीकी अंकेक्षण समिति या किसी अन्य संगठन का निर्माण नही किया जा सका जिससे निर्गमन पालिका ऑन तकनीकी विभागो मे बैठे अधिकारी कर्मचारी अपनी मोटी कमाई के लिए जनता के पैसे की बर्बादी के साथ भविष्य की परेशानी भी खड़ी कर रहे हैंऔर उसके बाद मे भीपैसे खर्च करकेचारो तरफ गंदगी फैली होने के बाद भी स्वच्छता का पुरस्कार खरीद कर अपने कुकर्मों भ्रष्टाचारो लूट डकैती को छुपाने और अधिक आवंटन पाने के लिए ले रहे हैं।

'मोहन सरकार सांप निकल गया लकीर पीट रही हैं'

'प्रधानमंत्री एंव मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जाँच की माँग'

इंदौर,इंदौर नगरनिगम मे 150 करोड़ का घोटाला करने वाली पाँचो फ़र्मों ने 2020 से 2024 तक मध्यप्रदेश मे कुल 16 नगरनिगमो मे से 12 नगरनिगमो मे लगभग 18 सौ करोड़ से ज़्यादा का फ़र्ज़ी बिल कांड करके जनता का पैसा लूट लिया हैं।

मोहन सरकार सारे मामले को दबाने मे लगी हुई हैं।

म.प्र.कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया की गोपनीय प्राप्त जानकारी अनुसार पाँचो फ़र्ज़ी बिल कांड मे शामिल फ़र्मों ने इंदौर नगरनिगम मे 150 करोड़ का घोटाला करने के साथ ही मध्यप्रदेश की 16 नगरनिगमो मे से 12 नगरनिगमो मे 18 सौ करोड़ से ज़्यादा की राशि फ़र्ज़ी बिलो के ज़रिये अधिकारियो एंव भाजपा के एक वरिष्ठ नेता एंव आईएस अधिकारी सहित पाँचो फ़र्मों के माफिया सिंडिकेट ने लूटी हैं।

कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया की गोपनीय सूचना के अनुसार पाँचो फ़र्मों ने संयुक्त रूप से षड्यंत्र रचकर इंदौर नगरनिगम मे 150 करोड़ से अधिक की राशि,भोपाल नगरनिगम मे 270 करोड़,सागर नगरनिगम मे 120 करोड़,जबलपुर नगरनिगम मे 220 करोड़,खण्डवा नगरनिगम मे 109 करोड़,बुरहानपुर नगर निगम मे 112 करोड़,ग्वालियर नगरनिगम मे 195 करोड़,उज्जैन नगरनिगम मे 145 करोड़,रतलाम नगरनिगम मे 114 करोड़,रीवा नगरनिगम 129 करोड़,देवास नगरनिगम 113 करोड़,सतना नगरनिगम 124 करोड़ राशि के फर्जी बिल बनाकर पाँच सालो मे लूट लिये हैं।

मध्यप्रदेश मे 12 नगरनिगमो मे 2020 से 2024 तक कुल 1801 करोड़ का घोटाला मध्यप्रदेश मे किया गया हैं।

इंदौर मे घोटाला उजागर होने के बाद से 12 नगरनिगम के अधिकारियो मे घोटाला छिपाने के लिए अफ़रा तफ़री मच गई हैं।

सूत्रो की जानकारी के मुताबिक़ मोहन सरकार सारा सच समझने के बाद भी सख्त कार्यवाही करने की जगह मामले को ठंडा करने मे लग गई है।

मध्यप्रदेश के इतिहास मे सबसे बड़ा घोटाला हैं जिसमे बिना काम बिना टेंडर फर्जी बिलो के ज़रिये 12 नगरनिगमो से 18 सौ करोड़ से ज़्यादा की राशि खुलेआम हड़पी गई हैं।

मुख्यमंत्री से पाँच प्रमुख माँगे हैं:-

(1) मध्यप्रदेश मे 18 सौ करोड़ से ज़्यादा के फर्जी बिल घोटाले मे सीबीआई जाँच कराये।पुलिस बिना दस्तावेज़ी सबूत अपराध साबित नही कर पायेगी।सीबीआई जाँच मे समस्त कड़ियो को जोड़ने के साथ डिजिटल सबूत एकत्रित करने के बाद ही मुख्य सरग़ना तक सीबीआई पहुँच सकेगी।

(2) 12 नगरनिगमो मे सेंट्रल एजेंसी से 2020 से लेकर 2024 तक का ऑडिट कराया जाये।ऑडिट सीबीआई की देखरेख मे किया जाये।स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी एंव विशेष निधि बजट मे जमकर फर्जी बिलो से राशि लूटी गई हैं।विशेष तौर पर इन बजट की जाँच होना चाहिए।

(3) 12 नगरनिगमो मे लेखा विभाग के अधिकारियो के फोन कॉल डिटेल डाटा लैपटॉप,बैंक एकाउन्ट,ट्रांजेक्शन जप्त किये जाये।अधिकारियो एंव शामिल अन्य व्यक्तियो द्वारा डिजिटल सबूत नष्ट लगातार किये जा रहे हैं।अतः 12 नगरनिगम के लेखा विभाग के रिकॉर्ड को तत्काल सील किया जाये।

(4) मोहन सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताये की इन पाँचो फ़र्मों को किसके कहने पर 12 नगरनिगमो मे फर्जी बिल कांड करने संरक्षण प्राप्त हैं। मोहन सरकार भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम उजागर करे।

(5) पाँच फ़र्ज़ी फ़र्मों के अलावा कितनी फ़र्ज़ी फ़र्मों के ज़रिये फ़र्ज़ी भुगतान बिल कांड 12 नगरनिगमो मे माफिया सिंडिकेट ने किया हैं,इसकी जाँच करायी जाये।

कांग्रेस महासचिव यादव के अनुसार इतना बड़ा घोटाला बिना राजनैतिक सहयोग के नही हो सकता हैं।

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार इस मामले मे जाँच कराने मे असक्षम सिद्ध हो रही हैं।

नेता अधिकारियो एंव माफियाओ ने फ़र्ज़ी फ़र्मों के ज़रिये मिलकर जनता का पैसा लूट लिया है।

कांग्रेस महासचिव यादव ने सारे मामले की जाँच सीबीआई से कराने हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हैं।

चीन के मोटे फायदे के लिए 10 सालों में सफाई, कैशलेस, नोटबंदी जीएसटी, तालाबंदी

पेज 1 का शेष

जिन भारी हथियारो जिन के संचालन मे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं इजरायल की हिब्रू और रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रेंच भाषा की सॉफ्टवेयर आज तक अपनी भाषा मे नही बदले जा सके हैं। तू कैसे उन हथियारो को युद्ध भूमि मे उपयोग किया जा सकेगा दूसरी तरफ जानबूझाकर हमारी सेना मे 40 लाख सैनिक हुआ करते थे जिन्हे खर्चा कम करने और देश की सीमाओ को कमजोर बनाकर चीन को सौंपने के लिए घटाकर पहले 15-16 मे 25 लाख पर, 17-18 मे 15 लाख और 19-20 मे 10 लाख पर जबरदस्ती सैनिको की सेवानिवृत्ति कर लाया गया। उसने अधिकारी से लेकर नीचे तक युद्ध के मैदान मे लड़ने वाले सैनिक भी थे बाद मे 18-19 मे अग्नि वीर योजना लाकर सेना को पूरी तरह से कमजोर कर बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि एक सैनिक वह अधिकारी को तैयार होने मे ही आधुनिक हर दिन बदलती युद्ध तकनीकी, कौशल, अयोध्या विस्फोटको गोला बारूद को समझने मैं ही 10 से 15 साल लग जाते हैं। 4 साल के अग्नि वीर मे तो रंगरूट से लेकर सूबेदार व अधिकारियो को हथियारो को समझाने चलाने साफ सफाई कर संचालन योग्य बनाए रखने, साथ छोटी मशीन गने, टैंक तोप वाहन वायरलेस संचार व्यवस्थाओं को संचालित करने युद्ध के मैदान मेअपनी रक्षा कर अधिकतम शत्रु को घात करने के रण कौशल को सीखने समझने और आत्मसात कर उसमे ढलने मे10 से 15 वर्ष का समयकाफी कम होता है।यही हाल उसने उन अयोध्या मे लगने वाले गोला बारूद मिसाइल टैंक तोप रॉकेटस पेट्रोल डीजल खाद्य चिकित्सा आदि की सामग्री का सेना के लिए जो 40 दिन कास्टॉक रखा और संभाला जाता था वह भी उसने घटकर 15 16 मे ही पहले 30 दिन फिर 25 फिर 15 और अब 10 दिन का कर दिया। इससे जनता अंदाज लगा सकती है जबकि चीन और पाकिस्तान से अगर युद्ध हुआ तो यह युद्ध 10-5 दिन का नही दोनो की लगभग चीन से 46 सौ और पाकिस्तान से 1600 किमी की लंबी सीमा पर महीनो और बरसो लग सकता है। 56 इंची डरपोक मोदी का इतना सब कुछ होने के बाद मे भी साफ झूठ बोलना कि हमारी सीमाओ पर मैं कोई नही घुसा है किसी ने अतिक्रमण नही किया है और विदेश मंत्री चोर ढीट, मक्कार मरियल हरामखोर जालसाज जयशंकर प्रसाद का यह बोलनाकि हम तीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ सकते हैं हमे इसराइल और वियतनाम से भी ज्यादा कमजोर सिद्ध करने के साथ देश की तीनो सेनाओ व जनता का मनोबल तोड़ना और कमजोर करना है। परंतु यहां तो सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत जहां भाजपा आरएस एस और सनातनी जो विशाल अखंड भारत की कल्पना कर नई लगाते है। फिर यदि अगले 5 साल मे मोदी पुनः सत्ता मे लौटता है तो पंजाब जम्मू कश्मीर का पूरा पूरा उत्तरी हिस्सा के साथ सिक्किम भूटान तिब्बत से लेकर असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, कोहिमा तक सब चीन को मोदी थाली मे सजा पुरस्कार मे दे देगा और इसके बारे मे उसकी विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भी मोदी की तरह खुले मे स्पष्ट कह दिया है कि हम चीन से लड़ने मे कामयाब नही है। परंतु धूर्तो की फौज एक तरफ इजराइल से दोस्ती निभाती है और दूसरी तरफ इजराइल से हथियार पेगासस सॉफ्टवेयर व रडार संचार संचालन सामग्री खरीदती है। उसकी प्रशंसा भी करती है पर सिखाती कुछ नही कि वह कैसे एक 70 लाख की आबादी का देशचारो तरफ से लेबनान, फिलिस्तीन, मिश्र आदि से घिरा होने के बाद मे भी अकेले ही सबसे लोहा लेने की क्षमता रखता है और यह 125 करोड़ की आबादी का देश उस चीन चीन को लाल आंखे दिखाने की भी औकात नही रखता है उल्टे ही अपने देश की बर्बादी करने उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने देश मे आते-जहां मोदी ने सफाई के नाम पर करोड़ छोटे व्यवसायियों ठेले वालो पद मार्गो पर व्यवसाय करने वालो को खत्म कर आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। उन दंपतियो के बच्चे ही भारत की जल, थल, वायु सेना के साथ हमारी परोक्ष अर्ध सैनिक बलों जिसमे सीआरपीएफ बीएसएफ पुलिस एनडीआर एफ आदि में भर्ती होकर घर अपराधिक प्रवृत्ति के नेताओ मंत्रियो के सुरक्षा बलो मे रक्षा के काम आते थे। उन सबको अनपढ़ गंवार जाहिल बनाने और भूखा मार कर मजबूर बनाने का षड्यंत्र रच दिया। आगे कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी मे देश के 5 करोड से ज्यादा छोटे लघु उद्योगो दुकानो बाजरो मंडियो को नष्ट कर 30 करोड़ लोगो को बेरोजगार बनाकर उनकी क्रय शक्ति खत्म कर जो पर्याप्त आई के कारण पेट्रोल-डीजल से लेकर डेढ़ हजार से ज्यादा वस्तु मे जीएसटी देती थी। एक तरफ सरकार ने अपना राजस्व खोया, युवा बल बर्बाद किया। जिसके दम पर मोदी पूरी दुनिया मे युवा शक्ति होने का ढिंढोरा पीटते थे, बेरोजगारी व भूख से मार 100 करोड़ लोगो को रु.1 किलो का गेहूं रु.2 किलो का चावल खिला भिखारी बना दिया। जिस देश आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ युवा बल को भी नपुंसक नकारा निकम्मा बना दिया। जो यदि भविष्य मे चीन पाकिस्तान से युद्ध करना भी पड़ा तो वह सेना मे अशिक्षित और कमजोर होने के कारण भर्ती होने लायक भी नही रहेंगे। दूसरी तरफ मोदी के सफाई कैशलेस नोटबंदी तारबंदी के षड्यंत्र ने देश के उद्योगो को नष्ट करने के साथ-साथ हम चीन की छोटी बड़ी सामग्री से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनो तक का आयात तक देश बनकर आज चीन से भारत 105 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात करने के बदले मे मात्र 28 से 30 अरब डॉलर का निर्यात कर पाता है। पर मोदी को तू ही सबके बदले मोटा कमीशन मिल रहा है उसको देश की बर्बादी से क्या और उसकाजीता जागता उदाहरण है पीएम केयर फंड मे सबसे ज्यादा सैकड़ो करोड़ का चंदा अप्पो वीवो श्यओमी जोमैटो स्विग्गी जैसी कंपनियो ने देने के साथ दो किस्तो मे डेढ़ सौ अरब डॉलर का और उनके नाम पर चीन ने बैंक आफ चीन खोलकर मोदी को रख दिया तो आखिर क्यो फिर जो भाजपा अबकी बार 400 पर का नारा लगा रही थी उसने पूरे जम्मू-कश्मीर से लेकर असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों मे अपने उम्मीदवार खड़े क्यो नही किया इसीलिए ना ताकि अगले 5 साल मे अगर चीन धीरे-धीरे करके घुसपैठ करते हुए नाम बदलकर हड़प ले तो उस पर या उसकी सरकार के सांसदो पर किसी प्रकार का कोई आंच ना आए और वह आसानी से थाली मे परोस कर चीन से मोटा कमीशन खाकर सारे के सारे जम्मू कश्मीर तिब्बत भूटान सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्यो को स्वयं ही मीडिया को तो खरीदा ही हुआ है। देश का टुकड़खोर भांड मीडिया के भेड़िये उन सब भाजपा की नाकामियो षड्यंत्रो पर कभी हुआ हुआ नही करते। कभी वहां जाकर सच्चाई नही जानतेना उसे पर कोई बातचीत करते मणिपुर जल रहा है। तो उनकी बला से, यह कर्मकांड पूरे उत्तरी जम्मू-कश्मीर और पूर्वी उत्तरी भारत को अशांत रखने का चिन्ह का उद्देश्य यही है कि वह परेशान होकर स्वयं ही उसे हिस्से पर अपना दावा और प्रशासन छोड़ दे और उसके लिए पूरा भुखेरा जन पार्टी गिरोह और उसकी आका देसी विदेशी पूंजी पतियो बहुराष्ट्रीय कंपनियो का राक्षस सेवा संघ चुनाव जीतने के बाद आंख मिचकर सपना के लिए तैयार बैठा है उसकी तरफ उसने आंख उठाने भी बंद कर दिया यही है सनातनियो का अखंड भारत जो जीत के बाद गिने चुने उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा तक सन् 2047 तक सिमट जाने की पूरी संभावना है अगर यही मोदी व इसके गिरोह के लोगो का शासन रहा तो। अभी वक्त है सोच समझकर वोटिंग कर अब मोदी को हकिया धकिया दो।

ईवीएम, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से क्या बदला और क्या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के 100 फ़ीसद मिलान की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, 'हमने याचिकाओं को सुना. इन याचिकाओं में पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की पुष्टि और इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वीवीपैट से निकली पर्चियों की 100 फ़ीसदी गिनती करवाए जाने की मांग की गई थी.'

'हमने मौजूदा प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा को ध्यान में रखते हुए इन सभी को खारिज कर दिया है.'

हालांकि ये फ़ैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई खास बदलाव करने के आदेश दिए हैं.

चुनाव आयोग की नज़र से देखा जाए तो उसके लिए फ़ैसले से मतदान आयोजित करने के तरीके में बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन कोर्ट ने आयोग से कहा है कि चुनाव के बाद की प्रक्रिया में वो कुछ नई प्रक्रियाएं अपनाए.

पहला निर्देश ये है कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील किया जाए. दूसरा ये कि चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद एसएलयू को कम से कम 45 दिन के लिए सीलबंद कर ही रखा जाए.

एसएलयू को पहले कंम्यूटर से जोड़कर इस पर चुनाव चिह्न लोड किए जाते हैं जिसके बाद वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिह्न और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

इन एसएलयू को खोला जाएगा और इसकी जांच उसी तरह की जाएगी, जिस तरह ईवीएम की होती है.

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट पर चुनाव चिह्न लोड करने के लिए एक से दो एसएलयू का इस्तेमाल होता है. चुनाव संपन्न होने के बाद इससे संबंधित किसी तरह की शिकायत के मद्देनज़र अब इन्हें इस्तेमाल के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा.

कोर्ट ने और क्या कहा

इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि उम्मीदवार चाहें तो ईवीएम के वेरिफ़िकेशन की मांग कर सकते हैं.

चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफ़िकेशन के लिए कह सकता है.

उम्मीदवार किसी संसदीय या विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5 फ़ीसदी ईवीएम के मेमोरी सेमीकंडक्टर की जांच की मांग कर सकता है.

उम्मीदवार की लिखित गुज़ारिश पर वेरिफ़िकेशन किया जाएगा, जिसे ईवीएम निर्माता के इंजीनियरों की एक टीम अंजाम देगी.

फ़ैसले के अनुसार, उम्मीदवार या प्रतिनिधि पोलिंग स्टेशन के नंबरों या सीरियल नंबरों के हिसाब से ईवीएम की पहचान कर सकते हैं.

हालांकि कोर्ट ने कहा कि वेरिफ़िकेशन के लिए गुज़ारिश चुनाव के संपन्न होने के 7 दिन को भीतर की जानी चाहिए और इसके लिए ख़र्च उम्मीदवार को ही उठाना होगा.

अगर वेरिफ़िकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग को उम्मीदवारों ये पैसा लौटाना होगा.

कोर्ट की सलाह और क्या नहीं बदला?

इसके अलावा कोर्ट ने सलाह दी है कि चुनाव आयोग इस सुझाव के बारे में 'जांच' कर सकता है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती में इंसानों की बजाय मशीन का इस्तेमाल किया जाए.

इसके लिए मशीन से निकलने वाली हर पर्ची पर एक बारकोड बनाया जाए जिससे इसकी गिनती आसानी से हो सके.

कोर्ट ने कहा कि यह एक तकनीकी पहलू है जिसके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं.

मतदाताओं की नज़र से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उनके लिए कोई बदलाव नहीं आया है.

जिस तरह ईवीएम के ज़रिए अब तक मतदान होता था आगे भी उसी तरह होता रहेगा, जिसमें 100 फ़ीसदी मशीन वीवीपैट से जुड़ी होगी.

इसके अलावा, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ईवीएम से होने वाली गिनती के वेरिफ़िकेशन के लिए पांच विधानसभा क्षेत्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी.

इस पांच चुनाव क्षेत्रों का चुनाव रैंडम तरीके से किया जाएगा.

इस मामले में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स ने वीवीपैट पर्चियों की 100 फ़ीसदी गिनती की मांग की थी.

दूसरे चरण में कितने फीसदी हुआ मतदान?

अंग्रेज़ी में छपने वाले द हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में करीब 61 फ़ीसदी वोटिंग हुई है.

दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ.

चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक वोटिंग पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा और मणिपुर में हुई जबकि सबसे कम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में हुई.

शुक्रवार शाम सात बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, त्रिपुरा 78.53 प्रतिशत, मणिपुर 77.18 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71.84 प्रतिशत वोटिंग हुई.

वहीं उत्तर प्रदेश में 53.71 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 53.84 प्रतिशत, बिहार में 54.91 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में करीब 55.77 प्रतिशत वोटिंग हुई.

वहीं छत्तीसगढ़ में 72.61 प्रतिशत और असम में 70.68 प्रतिशत वोटिंग हुई.

नोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने ईवीएम में दिए जाने वाले नोटा (नन ऑफ़ द अबव यानी किसी को भी नहीं) को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया है.

अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मतदाताओं को नोटा ऑप्शन देने के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयोग से जवाब तलब किया है.

बेंच में चीफ़ जस्टिस के अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे.

कोर्ट शिव खेड़ा की दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें ये मांग की गई थी कि जिन चुनाव क्षेत्रों में नोटा ऑप्शन को सबसे अधिक वोट मिलें, उन सीटों पर दोबारा चुनाव करवाए जाएं.

मौजूदा व्यवस्था में इस तरह के मामलों में नोटा के बाद जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर होता है, उन्हें ही विजेता घोषित कर दिया जाता है.

याचिका में कहा गया था कि नोटा को सबसे अधिक वोट देकर जिन उम्मीदवारों को जनता ने खारिज कर दिया उन्हें फिर से उम्मीदवार न बनाया जाए.

कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए चुनाव आयोग को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' के रूप में नोटा के बारे में जानकारी देने को लेकर जांच करनी चाहिए.

राहुल क्या अमेठी लौटने की तैयारी में हैं?

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन अहम सीटों पर मतदान संपन्न हुआ उनमें से एक केरल की वायनाड सीट है जहां उम्मीदवारों की सियासी किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है.

द टेलीग्राफ़ में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जाने-अनजाने ऐसा फ़ैसला ले लिया है जो राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है.

वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी दूसरे चरण के मतदान के खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर अपना ध्यान लगा सकते हैं. अमेठी में मतदान 20 मई को है.

राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? इसे लेकर मीडिया के कई हलकों में कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वो अमेठी से बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरें.

अखबार लिखता है कि अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास और आस-पास के बगीचे की साफ सफ़ाई करते देखे गए हैं. इसके अलावा उनके आवास के पास बगीचे में टेंट का सामान भी पड़ा है.

अखबार ये भी लिखता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं. हालांकि ये ज़रूर कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ें या न लड़ें, राहुल गांधी यहां चुनावी रैली ज़रूर करेंगे.

इसके साथ ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार के गढ़ रहे रायबरेली से प्रियंका गांधी बतौर उम्मीदवार अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं.

इससे पहले प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि यहां के वोटर 'गांधी परिवार से किसी को' यहां देखना चाहते हैं. हालांकि ये भी चर्चा है कि वो खुद चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं.

अमेठी में 2014 में राहुल गांधी ने 1.07 लाख वोटों से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को मात दी थी, लेकिन 2019 में खेल पलटा और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से शिकस्त दी.

लेकिन इस बीच इस तरह की खबरें हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो अधिक लोकप्रिय नहीं हैं.

मोदी ने लूट के लिये पौराणिक तीर्थों की पवित्रता नष्ट की

पेज 1 का शेष

दो नदियों वरुणा और असि के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। असि अब नाले के स्वरूप में है और गंगा का प्रदूषण तो पूरे देश में चर्चाओं में है।

देश की राजधानी भले ही नयी दिल्ली हो लेकिन देश की सांस्कृतिक राजधानी का तमगा वाराणसी को ही हासिल है। बड़े शहरों और महानगरों की तुलना में वाराणसी एक छोटा शहर है, लेकिन इसके बावजूद यहां करीबन 23 हजार छोटे-बड़े मंदिर हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि काशी को खुद भगवान् शिव ने बसाया था और यही कारण है कि काशी में सभी देवताओं का वास है।

कहा जाता है कि सन् 1194 में जयचन्द को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबउद्दीन ऐबक को वाराणसी पर अधिकार करने के लिये भेजा। इसके बाद हिन्दुओं के 1000 मन्दिर तोड़ गये और 1400 ऊंटों पर इस सम्पत्ति को लाद कर मोहम्मद गोरी के पास भेजा गया। ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को 'योजनाबद्ध तरीके से' दोहरा रहा है। आज एक बार फिर से काशी में 'विश्वनाथ कॉरिडोर' और 'गंगा पाथ वे' योजना के नाम पर प्राचीन मठ, मंदिरों को तोड़ा या उजाड़ा जा रहा है। 20 फुट चौड़े और करीब 300 मीटर लंबे दो कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के आसपास के पक्का महाल (पुराने बनारस) के करीब 300 पुराने मकान, जिनमें मठ, मंदिर भी शामिल हैं, ध्वस्त किए जाएंगे। यह योजना काशी के पुरातन इतिहास की कीमत पर लागू होगी। इस योजना के तहत आने वाला पूरा इलाका काशी के पौराणिक-सांस्कृतिक व इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खत्म होगा तो काशी की पहचान मिट जाने का अंदेशा है।

सिर्फ महापुरुषों से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, धरोहर और कई प्राचीन मंदिर भी इसकी जद में आएंगे। इस कॉरिडोर की जद में हजारों परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस इलाके में बसे हुए हैं और करीब 400 दुकानदार व उनसे जुड़े लोगों की आजीविका भी उजड़ जायेगी। इसके कारण नेमि दर्शनार्थियों, संतों, स्थानीय लोगों सहित काशी की परंपरा में जीने वालों में काफी आक्रोश है।

लेकिन प्रशासन के दबाव में या कहें कि सरकार विरोधी भावना का इजहार न करने के मौजूदा दबाव में कोई खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा। कहीं-कहीं विरोध के स्वर उठे भी हैं तो उसे तुरंत विकास विरोधी बताकर दबा दिया जा रहा है। इस योजना की जद में आने वाले भवनों को प्रशासन मोल-तोलकर सहमति से या दबाव बनवाकर खरीद रहा है और उसमें रहने वालों को बेदखल कर उसे ध्वस्त करा रहा है। खास बात ये है कि इनमें से कई मंदिर काशी की अंतरगृही परिक्रमा का हिस्सा हैं।

प्रशासन का दावा है कि केवल भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है मंदिरों या देव विग्रहों को नहीं। जबकि स्थानीय जानकार बताते हैं कि इस इलाके में लगभग हर घर में देव विग्रह हैं, मंदिर हैं, जो ध्वस्तीकरण के दौरान नष्ट हो गये, इनमें दर्शन, पूजा-पाठ आदि बंद हो गए। लोगों का स्पष्ट कहना है कि मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे वो निजी संपत्ति में ही क्यों न हो। उसे तोड़ना या नष्ट करना तो महापाप है। और ये काम ऐसे दल की सरकार के समय में हो रहा है जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार मानती है और इस पार्टी की सरकार के मुखिया खुद यहां से सांसद हैं, लेकिन अब उन्होंने रहस्यमय चुप्पी साध ली है। यहां से विस्थापित होने वाले कई परिवारों ने तो सरकार के रवैये से दुःखी होकर अपने आराध्य देव विग्रहों को भारी मन से टाट के बोरों में भरकर अपने साथ ले जाना ही उचित समझा।

गौरतलब है कि 2015 में राजस्थान के जयपुर में विस्तारीकरण के नाम पर 200 साल पुराने मंदिर तोड़ दिये गये और ये काम वहां भाजपा सरकार की सहमति से हुआ। इसी प्रकार अब काशी में मंदिरों, प्राचीन धरोहरों और काशी के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जबकि, यहाँ की गलियां, प्राचीन मंदिर और परंपरा को देखने-समझने ही यहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसे में सुविधा या विकास के नाम पर देव विग्रहों को तोड़ना या मंदिरों के स्वरूप को बिगाड़ना या प्राचीन धरोहरों को खंडहर में बदलना क्या सही और शास्त्र सम्मत है? प्रदूषण के चलते गंगा अपने घाट छोड़कर सिकुड़ चुकी है, घाट जर्जर होकर टूटने के कगार पर हैं। आखिर विकास के नाम पर सरकार गुमराह क्यों कर रही है? खुद मोदी ने कहा था कि जो गंगा नहीं संभाल सकते, वो देश क्या संभाल सकते हैं? काशी की जनता जवाब मांग रही है...

आम खाना किसे नहीं पसंद? इस फल को लोग बहुत पंसद करते हैंआम का सेवन गार्मियों के लिए लोकप्रिय है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम के फल की कई किस्में होती हैं जैसे लंगड़ा, दशहरी और चौसा आदि। इतना ही नहीं इसका सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी और ए के साथ जिंक और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं सेहत के लिए इसे खाने के फायदे।

फलों का राजा आम

आम (मैंगो) के गुणः

आम (मैंगो) में वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध कई सारे गुण होते हैं; इनमें से कुछ गुणों के बारे में नीचे बताया गया है:

- **इसमें एंटीऑक्सिडेंट गुण हो सकते हैं।**
- **यह एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम कर सकता है।**
- **इसमें मधुमेह-रोधी (एंटी-डायबिटिक) गुण हो सकते हैं।**
- **इसमें कार्डियो-प्रोटेक्टिव गुण हो सकते हैं।**
- **इसमें एंटी-एजिंग गुण हो सकते हैं।**
- **इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव हो सकता है।**

संपूर्ण स्वास्थ्य (ओवरऑल हेल्थ) के लिए आम (मैंगो) के संभावित उपयोगः आम (मैंगो) के कुछ संभावित उपयोगों के बारे में नीचे दिया गया है:

1. स्तन कैंसर के लिए आम के संभावित उपयोग

स्तन कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है, जो विश्व स्तर पर समय से पहले ही महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है। अब प्राकृतिक उत्पादों को कैंसर रोधी (एंटी-कैंसर) एजेंट की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जा रहा है। मैंगिफ़ेरा इंडिका, स्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) को नियंत्रित कर सकता है। बनर्जी एट अल ने 2015 में चूहों में होने वाले स्तन कैंसर ज़ेनोग्राफ़्ट, पर आम (मैंगो) के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि आम (मैंगो) में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स जैसे कि गैलिक एसिड, गैलॉयल ग्लाइकोसाइड और गैलोटेनिन में स्तन कैंसर को ठीक करने वाली कीमोथेराप्यूटिक क्षमता हो सकती है। इससे पता चलता है कि आम (मैंगो) स्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, इस तर्क को साबित करने के लिए अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है।

2. अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आम के संभावित उपयोग

अल्सरेटिव कोलाइटिस एक पुरानी सूजन वाली बीमारी (क्रोनिक इंफ्लेमेटरी कंडीशन) है जो कोलोन और रेक्टम को प्रभावित करती है। आम (मैंगो) में पॉलीफेनोल्स जैसे कि गैलोटेनिन और गैलिक एसिड होने के कारण यह सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। किम एट अल ने 2016 में प्रीक्लिनिकल कोलाइटिस मॉडल में आम (मैंगो) के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के नतीजे से पता चलता है कि आम (मैंगो) खाने से अल्सरेटिव कोलाइटिस को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, इस तर्क को साबित करने के लिए इंसानों पर अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है।

3. रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए आम के संभावित उपयोग

फल और सब्जियों में बायोएक्टिव तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो रक्त शर्करा (ब्लड ग्लूकोज़) के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इवांस एट अल ने 2014 में एक अध्ययन किया था जिसमें दिखाया गया कि आम (मैंगो) से महिलाओं और पुरुषों दोनों में रक्त शर्करा (ब्लड ग्लूकोज़) के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। आम (मैंगो) में टोकोफेरोल्स, कैरोटेनॉयड्स, डाइटरी फाइबर, एस्कॉर्बिक एसिड, गैलिक एसिड, क्वेरसेटिन और मैंगिफेरिन होते हैं। ये जैविक रूप से सक्रिय यौगिक (बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड) रक्त शर्करा (ब्लड ग्लूकोज़) के स्तर को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं। हालाँकि, इस तर्क को साबित करने के लिए अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है। अगर आपको उच्च रक्त शर्करा (हाई ब्लड ग्लूकोज़) की समस्या है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और खुद से कोई भी दवा न लें।

4. त्वचा और बालों के लिए आम के संभावित उपयोग

अगर आम (मैंगो) को सही मात्रा में खाया जाए, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन A होने के कारण आपके बाल स्वस्थ बनते हैं और त्वचा को पर्याप्त पोषण मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, आम (मैंगो) प्राकृतिक सनब्लॉक के रूप में काम करके हमारी त्वचा और बालों को पराबैंगनी किरणों (अल्ट्रावॉयलेट रेज़) के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। इसलिए, ऐसा माना जा सकता है कि आम (मैंगो) खाने से त्वचा और बालों को फ़ायदा होता है, लेकिन, इस तर्क को साबित करने के लिए इंसानों पर अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है।6 अगर आपको त्वचा और बालों से संबंधित कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और खुद से कोई दवा ना लें।

5. मैक्यूलर डिजनरेशन को नियंत्रित करने के लिए आम के संभावित उपयोग

मैक्यूलर डिजनरेशन, आँखों का एक सामान्य दोष है जिससे आँखों की रौशनी भी जा सकती है। आम (मैंगो) में एंटीऑक्सिडेंट जैसे कि ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन और विटामिन A भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मैक्यूलर डिजनरेशन से निपटने में मदद कर सकते हैं। आम (मैंगो) कैरोटीन से भी भरपूर होता है जो नज़र बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस तरह, हम कह सकते हैं कि आम (मैंगो) खाने से मैक्यूलर डिजनरेशन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, इन तर्कों को साबित करने के लिए अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है।

6. पोषक तत्वों के सेवन (न्यूट्रिएंट इन्टेक) पर आम के संभावित उपयोग

आम (मैंगो), आपके आहार में पोषक तत्वों को पाने का एक अच्छा स्रोत होता है। आम (मैंगो) खाने और ना खाने वाले लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति के आंकड़े NHANES डाटाबेस से लिए गए थे। जिसमें पाया गया कि जो लोग आम (मैंगो) खाते हैं उनके शरीर में आम (मैंगो) ना खाने वाले लोगों की तुलना में मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलेट, विटामिन A, C और E और डाइटरी फाइबर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। इससे माना जा सकता है कि आम (मैंगो) खाने से पोषक तत्वों को ग्रहण करने और आहार की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, इन तर्कों को साबित करने के लिए अभी और ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है।

7. आम के अन्य संभावित उपयोग

आम (मैंगो) मोटापे (ओबेसिटी) से पीड़ित लोगों में वज़न कम करने में मदद कर सकता है।

कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के नाते, यह नज़र में सुधार करने में मदद कर सकता है।

आम (मैंगो) में एमाइलेज,जो खाने को तोड़ने में मदद करता है, मौजूद होने के कारण यह पाचन शक्ति में सुधार करने में मदद कर सकता है।

आम (मैंगो) में विटामिन A और C मौजूद होने के कारण यह प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) बढ़ाने में मदद कर सकता है।

यह आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल (हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन) के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

हालाँकि ऐसे कई अध्ययन किए गए हैं जो कई परिस्थितियों में आम (मैंगो) के फ़ायदों के बारे में बताते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर आम (मैंगो) के फ़ायदों को साबित करने के लिए अभी और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

आम सिर्फ़ पका हुआ ही स्वादिष्ट नहीं लगता बल्कि कच्चा, पकाया हुआ और प्यूरी के रूप में भी यह बेहद पसंद किया जाता है। कच्चे आम का अचार बनाया जाता है तो इसे सुखाकर अमचूर पाउडर, खटाई या फिर आम की चटनी का स्वाद भी लिया जा सकता है। भारतीय भोजन में आम के अनेक रूप देखे जा सकते हैं – मीठा अमरस, खट्टा-मीठा अमावट या आम पापड़ और मैंगो हलवा, खीर, कढ़ी और दाल में भी आम को डालकर पकाया जाता है यानी आम जिस भी रूप में हो, कोई भी खाने से मना नहीं कर सकता।

आम के 7 नए स्वाद, जो झटपट तो बनेंगे ही, मेहमानों का भी दिल जीत लेंगे। तो देर किस बात की...ट्राई कीजिए आम की इन लज़ीज़ रेसिपीज़ को।

आम को कैसे इस्तेमाल करें?

इस अत्यंत बहुमुखी फल का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

आम (मैंगो) को अच्छे से धोने और छिलने के बाद सीधे ही खाया जा सकता है। इससे जूस, जैम, जेली, चटनी, आइसक्रीम और स्मूदी भी बनाई जा सकती है। किसी भी हर्बल सप्लीमेंट या आम (मैंगो) को ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना आधुनिक दवाओं (मॉडर्न मेडिसिन) के साथ चल रहे किसी भी इलाज को बंद ना करें और ना ही उन्हें आयुर्वेदिक/हर्बल दवाओं से बदलें।

आम के दुष्प्रभाव

आम (मैंगो) खाने के कुछ दुष्प्रभावों के बारे में नीचे दिया गया है:

आम (मैंगो) की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें खाने से कुछ लोगों को गले में दर्द या एलर्जी (पेट दर्द, छींक आना और नाक बहने) की समस्या हो सकती है। ज़्यादा आम (मैंगो) खाने से पेट में दर्द, अपच (इनडाइजेशन) और दस्त जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आपको आम (मैंगो) से किसी तरह की कोई एलर्जी (प्रतिकूल प्रभाव) होती है, तो इसे खाना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें जिन्होंने आपको आम (मैंगो) खाने की सलाह दी है। वे आपके लक्षणों के हिसाब से आपको सही सलाह देंगे।

आम के साथ बरती जाने वाली सावधानियां

आम (मैंगो) को अगर नियंत्रित मात्रा में खाया जाए तो इसे खाना फ़ायदेमंद होता है। हालांकि, नीचे दी गई स्थितियों में कुछ सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए:

आम (मैंगो) को खाने से पहले एक घंटा पानी में रखने की सलाह दी जाती है। इससे आम (मैंगो) में मौजूद विटामिन और मिनरल का अवशोषण बढ़ जाता है। अपने भोजन के साथ आम (मैंगो) को ना खाने की सलाह दी जाती है।

आम में कैलरी

100 ग्राम आम में 60 किलोकैल कैलरी होती है। हमारी रोज़मर्रा की कैलरी का सेवन प्रमुख रूप से हमारी आयु, लिंग, वज़न और गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। माना जाता है कि वयस्कों के लिए हर रोज कैलरी की आवश्यकता 1,600 से 3,000 तक होती है। छिलके के बिना एक आम लगभग 200 कैलरी देता है, जो वयस्कों के लिए हर रोज़ की औसत कैलरी का लगभग 10 प्रतिशत है। इसमें विटामिन ए, सी, बी-6 और पोटैशियम होता है। आयुर्वेद के अनुसार, कच्चे या पके, दोनों तरह के आम का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह एक हाई कैलरी युक्त और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फल है, जो एनर्जी का अच्छा स्रोत बनाता है।

1. चिल्ड मैंगो चीज़केक

यदि आप चीज़केक पसंद करते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। मैंगो चीज़केक की इस अनोखी रेसिपी के साथ अपने जायके को बढ़ाएं। यह रेसिपी हंग कर्ड, क्रीम और क्रीम चीज़ के साथ तैयार की जाती है। सबसे पहले बिस्किट के चूरे में कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसे केक मोल्ड में दबाकर फैलाएं ताकि बेस तैयार हो सके। क्रीम चीज़ डालें। ऊपर से हंग कर्ड और व्हिप्ड क्रीम फैलाएं। अब आम की स्लाइसेज़ काटकर फैलाएं। ठंडा कर खाएं।

मैंगो चीज़केक जल्द बनने वाली रेसिपी है। पार्टी में कुछ अलग हटकर बनाना चाहती हैं तो इसे बनाएं। चिल्ड सर्व करें।

2. आम श्रीखंड

घर पर मिठाई लाना बंद कर चुकी हैं तो कोई बात नहीं। घर पर ही आप आम से श्रीखंड जैसा टेस्टी डेज़र्ट तैयार कर सकती हैं। इसके लिए एक कप हंग कर्ड में मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह मिलाएं। दूध में भिगोया हुआ केसर ऐड करें। ऊपर से बारीक़ कटे आम के टुकड़े मिलाएं। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स को बारीक़-बारीक़ काटकर मिलाएं। ऊपर से मैंगो सीरप भी डालें।

श्रीखंड में चीनी या शहद न मिलाएं। दही और आम की अपनी मिठास ही इस डिश को स्वीट बनाती है। ऊपर से मैंगो जैम ऐड करें।

3. मैंगो स्मूदी

आम की स्मूदी के साथ इस गर्मी को मात दे दें। 2 आम का पल्प, 1 कप ठंडा दूध या 1 कप हंग कर्ड और एक टेबलस्पून शहद डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड करें। इसमें केसर और कुछ पुदीने की पत्तियां मिलाएं ताकि इसका स्वाद आपके जायके को बढ़ा दे।

मैंगो स्मूदी के स्वाद को बढ़ाने के लिए चॉकलेट चिप्स या वैनिला आइसक्रीम ऐड करें। ये दोनों ही स्वाद स्मूदी को स्वादिष्ट बनाएंगे।

अन्य फलों की तुलना में, आम मीठा होता है और फाइबर में कम होता है इसलिए आम का सेवन कम मात्रा में ही करें। रिसर्च के अनुसार एक वयस्क के लिए रोज़ाना 2 मीडियम आम का सेवन पर्याप्त है।

4. मैंगो आइसक्रीम

मैंगो और कोकोनट आइसक्रीम के कॉम्बो से आप बड़े से लेकर बच्चों तक का दिल जीत सकती हैं। इसके लिए 2 कप मैंगो पल्प को गाढ़ा करें। हेवी कोकोनट क्रीम में आधा कप गाढ़ी क्रीम और दूध मिलाएं। थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। आइसक्रीम मोल्ड में पहले मैंगो पल्प डालकर फ्रिज में जमाएं। फिर कोकोनट का मिश्रण डालकर रात भर जमाएं।

इससे कुल्फी और स्टिक दोनों तरह की आइसक्रीम बनाई जा सकती है। पार्टी में इसे बनाएं और बच्चों और बड़ों से तारीफ़ पाएं।

5. ग्रिल्ड टर्की टाको विद मैंगोज़

टाकोज़ हर रूप में अच्छा लगता है। अगर इसकी स्टफिंग में आम को ऐड कर लिया जाए तो इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। टाको बनाने के लिए टॉर्टिया लें। इसमें टर्की मीट के साथ आम के कुछ टुकड़े डालकर स्टफिंग तैयार करें। ऊपर से शलजम और हैलेपीन्यो डालें। चाहें तो पुदीने की कुछ पत्तियां भी ऐड की जा सकती हैं। तैयार है टेस्टी एंड यम्मी टाको।

टाको का मजा लेना है तो कॉर्न टॉर्टिया के साथ इसे बनाएं। तवे पर इसे सेंक कर मोल्ड में रखें ताकि यह थोड़ा मोल्ड हो जाए।

6. कोकोनट पैनकेक विद मैंगो

पैनकेक का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भाता है। इन पैनकेक्स को नारियल डालकर बनाएं और ऊपर से मैंगो जैम और मैंगो के टुकड़ों के साथ सर्व करें। आपके मेन्यू में एक डिश जुड़ेगी और सबको स्वादिष्ट भी लगेगी। एक कप आटे में मैंगो पल्प डालकर गाढ़ा घोल बनाएं। तवे पर तेल डालकर पैनकेक बनाएं और सर्व करें।

मैंगो पैनकेक के स्वाद को थोड़ा अलग बनाना चाहें तो इसके बैटर में कोकोनट फ्लेक्स और सौंफ को ऐड करें।

7. मैंगो सालसा

नाचोज़ के साथ अगर मैंगो का टेस्टी व हेल्दी साल्सा मिल जाए तो समझें कि दिन बन गया। इसके लिए पके आम को बारीक़ काट लें। आधा बारीक़ कटा प्याज, बारीक़ कटी मिर्च, बारीक़ कटा खीरा, स्लाइसेज़ में कटी हैलेपीन्यो, 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर मिलाएं। ऊपर से पुदीना काटकर मिलाएं। इस डिश को नाचोज़ के साथ सर्व करें। ●

मैंगो सालसा घर में आसानी के साथ बनाया जा सकता है। कुछ लोग इसे कच्चे आम के साथ भी बनाते हैं। इसे ट्राई करें।

मोदी के 10 वर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन ले, इशारे पर नाच

भारत को बना दिया दिहाड़ी मजदूरों का देश

भारत अब दुनिया के उत्पादक नहीं चीन के उपभोक्ता, केंद्र व राज्यों के सरकारी विभाग भी मजदूर चला रहे

धन-धान्य व उपजाऊ भूमि से भरपूर, अपार खनिज संपदाओं से युक्त और सबसे बढ़कर 70 करोड़ से अधिक की युवा आबादी वाले हमारे देश भारत को कॉरपोरेट लूट व मुनाफे के लिए 'लेबर चौराहे' में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह प्रत्येक शहर में स्थित लेबर चौराहा पर दिहाड़ी मजदूर मिला करते हैं। आज ठीक उसी तरह देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, सरकारी दफ्तरों व कारखाने के लिए डाटा ऑपरेटर और कुशल श्रमिकों का भी बाजार लगने लगा है, जहां कॉरपोरेट कंपनियां मनमाफिक लोगों को कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट अथवा अपने प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक हायर (भर्ती) करती हैं।

और समय पूरा होने या प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद फायर कर देती हैं। पहले इन्हें साइबर कुली भी कहा गया था, लेकिन अब इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट व इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं। इन हायर स्किल्ड लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों व सरकारी संस्थानों के बीच कोई श्रम कानून किसी तरह की दखल नहीं दे सकता, उसी तरह जैसे लेबर चौराहों के दिहाड़ी मजदूरों का कोई श्रम अधिकार नहीं होता। इसमें एम्स और जेएनयू जैसे बड़े रिसर्च संस्थान, सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

दरअसल भारत में बेरोजगारी के कई स्तर हैं। एक तो वह जो उच्च शिक्षित-शिक्षित और अति कुशल-कुशल बेरोजगारी है, जिसमें बच्चे पढ़ाई पूरी करते-करते प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना, क्लर्की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और किसी तरह नौकरी किए जा रहे हैं।

दूसरा वह शिक्षित तबका है, जिन्हें पढ़ाई पूरी करने और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और वह उम्र अधिक हो जाने के कारण हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या कोई छोटा-मोटा काम करके जीविकोपार्जन करते हैं। अति कुशल और कुशल में आईआईएम, बीटेक, एमटेक, और पीएचडी के अलावा पॉलिटेक्निक व आईटीआई डिग्री डिप्लोमा होल्डर लोग हैं। इसमें भी बड़े संस्थानों से कोर्स पूरा करने वालों को कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है।

कुकुरमुत्तों की तरह हजारों की संख्या में उग आए उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से भी प्रतिवर्ष निकल रहे लाखों बच्चे अति सामान्य वेतन पर कंपनियों में नौकरी करते हैं, जिसमें वह पढ़ाई के लिए, लिए गए लाखों रुपए के लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं। शिक्षित-अशिक्षित और कुशल-अकुशल बेरोजगारी का संकट देशव्यापी और व्यापक है, जो भयावह सुप्त ज्वालामुखी जैसा है। युवाओं का आक्रोश रह-रह कर शहरों पर भड़क उठता है, जो ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट का आगाज़ हो सकता है।

सबसे खराब स्थिति में वह अर्ध कुशल और अकुशल मजदूर हैं, जो निर्माण क्षेत्र से लेकर छोटी-छोटी कंपनियों में न्यूनतम वेतन के अभाव में काम कर रहे हैं। अथवा रेहड़ी- खोमचा लगाने और रिक्शा-ठेला खींचने का काम करते हैं। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में लगभग 36.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से 61.5% कृषि, 20% उद्योग और 18.5% विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं। ज्ञात हो कि कृषि कार्य बल में ऐसे भी किसान हैं, जिनके पास सीमांत से लेकर बड़ी जोत वाली भूमि है।

इनमें बड़ी संख्या भूमिहीन मजदूरों की है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 14 करोड़ था। निश्चित रूप से यह संख्या काफी बढ़ चुकी है। इसके बाद मोदी सरकार ने कोई जनगणना नहीं कराई। करोड़ों भूमिहीन कृषि मजदूर गांव के अलावा शहरों में भी मौसमी काम के लिए आते हैं।

मनरेगा में औसतन 50% कार्य दिवस का काम ही उनको मिलता है और शहरों में भी उन्हें सरकार द्वारा घोषित वेज नहीं मिलता। एनएसएसओ सर्वे के अनुसार 2015-16 से वर्ष 2020-21 में नीचे से 50% की आबादी की आमदनी 14.4% से घटकर 9.8% हो गई। प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि या तो एकदम नहीं हुई या महंगाई की तुलना में दो-चार प्रतिशत ही बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण कार्य बल के 24.6% आबादी को एक दिन में 100 रुपए से भी कम की आमदनी हो रही है और शहरी कार्यबल के 10% लोगों की आमदनी रु.100 से कुछ ही अधिक है।

देश आजादी के बाद पहली बार पूर्ण और अर्ध बेरोजगारी के भयावह संकटों से जूझ रहा है, लेकिन आरएसएस-बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास इससे संबंधित कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। सरकार ने बीते एक दशक में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय उन्माद को भड़काया है। उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा

पैदा हो रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या और विकास दर संबंधी आंकड़े जारी करने वाली संस्थाओं और संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है या उनके कामकाज को निष्प्रभावी बना दिया गया है।

अब सरकार को गोएबल्स फार्मूले के तहत प्रत्येक विषय पर देश को भ्रमित करने और प्रोपेगंडा करने का मौका मिल गया है। अब केंद्र सरकार भाषणों में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी समाप्त करने के दावे कर रही है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के हवाले से (सरकार का एचएमवी संस्थान) दावा किया कि 25 करोड़ लोग बीते 9 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को प्रमुख मुद्दा बना रहा है और अपने घोषणा पत्र में नौकरियां देने का वायदा कर रहा है। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में बेरोजगारी शब्द का भी उल्लेख नहीं है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने वर्ष 2017-18 में भारत की बेरोजगारी दर 45 वर्ष के उच्चतम स्तर 6.01% पर पहुंचने संबंधी रिपोर्ट अनाधिकारिक तौर पर जारी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने यह कह कर खारिज कर दिया कि उसके आंकड़े वास्तविकता के आधार पर नहीं जुटाए गए हैं। उसी एनएसएसओ ने पिछले माह मार्च 2024 में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई है।

इस रिपोर्ट पर सरकार प्रोपेगंडा कर रही है। वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) ने 26 मार्च 2024 को जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बेरोजगारों में 83% युवा हैं और कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2000 के मुकाबले पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2000 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.02% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें दसवीं या समकक्ष शिक्षित युवाओं की संख्या शामिल नहीं है।

आईएलओ की रिपोर्ट पर सरकार खामोश है। इस तरह बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रोक दिया गया है और मनमाने ढंग से आंकड़ों को तैयार कर प्रोपेगंडा किया जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अनुमान के अनुसार भारत में केवल 20% सैलरी वाली नौकरियां दी जा रही हैं। शेष नौकरियों में जितने दिन काम उतने दिन के ही वेतन का प्रावधान है, जिन्हें साप्ताहिक अवकाश तक उपलब्ध नहीं है। अवकाश लेने पर दिहाड़ी मजदूर की तरह वेतन काटे जाने का प्रावधान है।

गोएबल्स प्रोपेगंडा के तहत आरएसएस- बीजेपी की सरकार दावा कर रही है कि भारत दुनिया में पांचवीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और चंद वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यहां एक सवाल उठता है कि सर्वाधिक अरबपतियों वाले देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उनका जीवन स्तर कैसा है? वास्तविकता यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के नागरिकों से भी कम है।

भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जिन देशों को पीछे छोड़ना है उनके नागरिकों की आय और जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए रोजगार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधा और कुपोषण से निपटने के लिए काम करती है। आरएसएस-भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले शासक वर्गों की दूसरी पार्टियां कम से कम यह सब करने का दिखावा करती थीं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के मुनाफे और गोएबल्स के प्रोपेगंडा पर काम कर रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में केंद्र और राज्य सरकारों सहित रेलवे, सेना, चिकित्सा, शिक्षा, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बलों और अनेक सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों की संख्या 60 लाख से अधिक है। फिर इन पदों को कई वर्षों से नहीं भरा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार उपरोक्त सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण कर चुकी है या कर रही है और जो बाकी हैं उन्हें भी तेजी से निजी क्षेत्र को सौंपा जाना है। सेना में अग्नि वीर मॉडल को इसी रूप में देखना चाहिए। यह सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस बलों में आने वाले वर्षों में ठेका नौकरी की शुरुआत का संकेत है।

एशिया भर में प्रतिष्ठित एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान में भी फैकल्टी और डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाने लगा है। दिल्ली सहित देश के अधिकांश हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ठेके पर रखे जाने लगे हैं। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत देश के बड़े शिक्षण संस्थानों, उच्च प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों कॉलेजों और स्कूलों को देसी-विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपा जाना है। रेलवे में अधिकांश नौकरियां पहले ही ठेके पर दी जा चुकी हैं। दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्रों को सौंपा जा चुका है। आरएसएस-भाजपा सरकार की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।

दरअसल मोदी सरकार कॉरपोरेट को सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर देश को ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की ओर ले जाने पर आमादा है। इसके लिए वह अपने एक दशक के शासन काल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती रही है और कॉरपोरेट को उसके फासिस्ट एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। बल्कि भाजपा आज सत्ता के जिस केंद्र में पहुंची है उसके लिए कॉरपोरेट ने डेढ़ दशक से प्रयास किया है।

भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर आम लोगों में हमेशा से एक ललक रही है। इसकी बड़ी वजह निश्चित वेतन, प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता, वेतन बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाएं, अवकाश और रिटायर होने के बाद पेंशन का प्रावधान था। इससे पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के पूर्व 8 वे दशक तक निजी क्षेत्र की कंपनियां भी श्रम कानूनों के तहत निश्चित वेतनमान, वेतन बढ़ोतरी और अन्य सुविधा देती थी।

दरअसल एक निश्चित वेतन और नौकरी में स्थायित्व से जो आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा एक परिवार को मिलती थी। अब वह समाप्त हो गई है। सभी तरह की नौकरियां ठेके पर जा चुकी हैं या जाने वाली हैं। सैलरी वाली नौकरी से देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति भी दिखाई देती है।

अपने निश्चित वेतन में एक परिवार अच्छे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद आवास की व्यवस्था करता है। वह उपभोक्ता वस्तुओं कपड़े, वाहन आदि उत्पादों की खरीद पर भी खर्च करता है। इससे देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का पूरा एक चक्र शुरू हो जाता है। कॉरपोरेट मीडिया बताता है कि नोट बंदी, कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के बावजूद मकान और गाड़ियां बिक रही हैं।

यह देखने की बात है कि वाहनों में महंगी और लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं और आवास भी करोड़ों रुपए से अधिक कीमत वाले बिक रहे हैं, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों की बड़ी संख्या का मासिक वेतन 25 से 50 हजार रुपए के बीच है। ऐसे में उनकी क्षमता लग्जरी वाहन और करोड़ों का घर खरीदने की नहीं है। 10 से 25 लाख रुपए की कीमत वाले मकान और चार-पांच लाख रुपए वाली गाड़ियां बाजार से नदारद हैं, जबकि रोजगार कर रहे लोगों में निम्न मध्य आय वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है।

केंद्र और राज्यों में दिसंबर 2022 में 80 लाख 50 हजार 977 और केंद्र सरकार के अधीनस्थ विभागों में 9 लाख 10 हजार 153 स्वीकृत पद रिक्त थे। आर्थिक उदारीकरण से पूर्व रेलवे में लगभग 16 लाख स्थाई और 3 लाख के आस-पास ठेके पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर होते थे। आज रेलवे में यह संख्या अनुमानित 11 लाख से कम है।

उसमें भी बड़ी संख्या ठेका वाले श्रमिक और कर्मचारी हैं। देश में रिक्त सरकारी पदों के आंकड़े समय-समय पर सरकार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के सवालों के जवाब में देती रही है। दिसंबर 2021 में रेलवे में 3 लाख 62 हजार, थल सेना में एक लाख 75 हजार, वायु सेना में 8000, नौसेना में 12000, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में 2 लाख, केंद्र सरकार के अस्पतालों में एक लाख 68 हजार, आंगनबाड़ी में एक लाख 76000, केंद्रीय विद्यालयों में 18000, नवोदय विद्यालयों में 16000, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20 हजार पद रिक्त थे।

अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 1662 आईटीआई, 7412 एनआईटी, 4662 आईआईएम, 946 सीबीआई, 1342 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 190 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 1085 रक्षा क्षेत्र में अधिकारियों, 88 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर शुल्क बोर्ड, 2127 आईबी, 123 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के दफ्तरों में, 1403 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 250 प्रवर्तन निदेशालय, 114 विदेश मंत्रालय और 190 केंद्रीय सचिवालय में पद रिक्त थे. इसके अलावा

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में जजों के लगभग 5000 पद रिक्त थे। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 8 लाख 37 हजार पद रिक्त थे, तो 28 राज्यों के पुलिस कर्मियों के 5 लाख 31 हजार स्वीकृत पद रिक्त थे।

सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को देखते हुए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023' रिपोर्ट का कहना है कि देश में युवा स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 42.3 प्रतिशत के स्तर पर है। सरकार की दलील रही है कि देश में रोजगार की जरूरत के मुताबिक लोग शिक्षित नहीं हैं। अथवा उनमें आवश्यक स्किल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि स्नातक या उच्च योग्यता वाले युवा जिनकी उम्र 25 से 29 वर्ष के बीच है उनमें बेरोजगारी दर.8 प्रतिशत है। इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर की योग्यता वाले और 25 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों में बेरोजगारी दर 21.4% है।

बेरोजगारी पर केंद्रित 'सीएमआई' की रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 करोड़ स्नातक हैं। बड़ी संख्या बीटेक और आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिग्री व डिप्लोमा होल्डर्स की है। सरकार अप्रशिक्षित और अन प्रोफेशनल डिग्री को बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताती है और इसके लिए स्किल इंडिया जैसा फर्जी अभियान वर्षों से चलाया जा रहा है, लेकिन सरकारी दफ्तरों, पीएसयू और कॉरपोरेट कंपनियों में बीटेक, एमटेक, एमबीए डिग्री धारक युवा 20 से 50000 रुपए की ठेका नौकरी कर रहे हैं।

यह ठेका अवधि पूरी होने अथवा कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सेवा से निकाल दिए जाते हैं। कानून के बावजूद इनका कोई ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड नहीं होता। विश्वविद्यालयों, उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों और स्कूल व कॉलेज में तो अब एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है और वहां प्रति घंटा एक क्लास लेने के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यह स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की है।

आरएसएस-भाजपा सरकार आजादी के 75 वर्ष पर अमृत काल मान रही है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ख्वाब देश को दिखा रही है। इसके विपरीत 'विश्व असमानता डेटाबेस रिपोर्ट' के अनुसार भारत की 1 प्रतिशत आबादी के पास आय की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका भी भारत से पीछे है। दुनिया आश्चर्यचकित है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के भोजन पर आश्रित हैं। वहां दुनिया के सर्वाधिक अरबपति कैसे रहते हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि देश में किसी भी मामले में वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में दुनिया भर की तमाम संस्थाएं जो सर्वे या रिपोर्ट जारी करती हैं। उन्हीं को पिछली सरकारी रिपोर्ट के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश राज में जो आर्थिक असमानता थी, स्थिति अब और खराब है। कोरोना महामारी के बाद जब देश और दुनिया में आर्थिक तंगहाली थी, तो भारत में 2022-23 में शीर्ष एक प्रतिशत आबादी के पास 22.6% आय और 40.01% संपत्ति थी।

रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद आठवें दशक की शुरुआत में आर्थिक असमानता में गिरावट आई थी। इसके बाद वर्ष 2000 से यह आसमान छूने लगी है। रिपोर्ट यह भी सवाल करती है कि इस असमानता के कारण कब तक देश बड़े स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक उथल-पुथल के बिना बना रह सकता है ?

रिपोर्ट के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे बुनियादी सवाल जो युवाओं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं से सीधे-सीधे संबद्ध हैं और वह सभी बीते वर्षों में आंदोलित होते रहे हैं। आज जरूरत उन सभी सवालों और प्रभावित तबकों को जोड़ने और साझा संघर्ष की है। ताकी आरएसएस-बीजेपी के फासिस्ट राज को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।

जनता ने कम किया जमा कर रखना बैंकों में बचत

पेज 1 का शेष

भाई चल ही रहा था कि 8 नवंबर 2016 को उसने नोटबंदी की घोषणा कर काले धन को खत्म करने के षड्यंत्र के नाम परलोगों के घर में रखे हुए बचत के धन व 500 व रु.1000 के नोटों को भी बैंक में शून्य पर जनधन खातों के खुल वाने नाम पर पुराने नोटों को जनता के 50 करोड़ खाते खुला और लगभग रुपए 25 से 30 लाख करोड़ न्यूनतम शेष सेवा श खातों के रखरखाव का शुल्क के नाम पर हजम कर 50 करोड़ गरीब जनता की बचतें हजम कर कंगाल बना अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का नहीं लगभग 60 लाख करोड़ रु के माफ किए गए कर्ज की वसूली कर बैंकों को डूबने से बचाया गयाइससे भीआम जनताने अपनी बचातों को बैंकों में रखना बंद कर दिया फिर जनता के बैंकों में जमा खातों पर निगाह रखने के लिए मोदी की खोटी नियत ने जैसे ही रु. 2लाख से ज्यादा की बचत जमा होने या रहने पर न केवल सभी बैंकों, लघु बचतों के डाकघरों ने भी पैन कार्ड मांगना शुरू कर दिया और ना रहने पर लेन देन रोकने चेक बुक न देने जमा स्वीकारने भुगतान करने परोक लगाने के कारण भीआम निम्न मध्यम वर्गी व मध्यम वर्जन ने बैंकों व डाकघरों से दूरी बनाना शुरू कर दी। फिर हरामखोर जल सच चोरकट्टों की फौज जनता को नंगा करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए उसने उसके ऊपर दंड लगाना भी शुरू कर दिया। जबकि भूखे वीडियो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चंदा खाने वाले जालसाज हरामखोर डकैतों की औकात नहीं हुई, की सबसे पहले पैन कार्ड आधार कार्ड, बैंकों की जमा व अन्य सभी प्रकार का लाखों गीगाबाइट में तैयार होने वाला प्रतिदिन का डाटा अपने यहां रोक कर जनता के डाटा की सुरक्षा कर सकें। वैसे मोदी की खोटी नियत ने ही पूरी कोशिश की थी की जनता को पूरी तरह से सफाई कैशलेस, नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी में परिवार की महिलाओं के मंगलसूत्र बिकवा कर पूरी तरह से नंगा कर सड़क पर भीख मांगने के लिए बैठा दें जो अगले 5 साल में देश के 95% लोगों को अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर भीख मांगने और दाने-दाने के लिए मोहताज करने के लिए वह चांडाल पूरी करने की कोशिश करेगा यदि सचमुच 400 पार हो गई।

जनता की रिजर्व बैंक के बच्चों की कम होने कारे अचल संपत्ति खरीदने में निवेश करने का मूल कारण यही है कि बैंकों ने अपने ही 100 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ता को चारों तरफ से गिरकर आधार कार्ड पैन कार्ड को जोड़ने वहां जमा करने के लिए विवश करने के साथ उनके उत्तर को बेचने डार्कनेट और उपलब्ध होने के कारण 23-24 में डाले गए 90 लाख से ज्यादा जो कि पुलिस व बैंकों के पास लिखित शिकायत के रूप में पहुंचे जबकि यह आंकड़ा लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि 60% ग्रामीण व 40% शहरीय लोगों के खातों में जो डकैतियां हैकर्स और साइबर अपराधी डाल रहे हैं। वह इस विश्वास मेंजी रहे हैं कि हमारे खाते में ऐसा नहीं होगा पर सभी राष्ट्रीयकृत सरकारी, निजी सहकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ भी सेंड हैकर्स से कमीशन के माध्यम से पैसा खाता है जानकारियां उपलब्ध करवाता है जिसके ऊपरन केवलबैंको के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस हिस्सेदारी करके जमा कर्ता को लूट डकैती या जलसा जी के भनक लग जाने के बाद में भी 90% साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायतों ना तो बैंक लेते हैं और ना सायबर पुलिस, तो समझा जा सकता है कि लगभग 10 करोड़ खातों में हर वर्ष खुलकर डकैती डाली जा रही है। और पूरी ठगाई जनता कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए वह बैंकों से दूर हुई जबकि रिजर्व बैंक ने अपनी व सरकार की कमियों नाकामियों को छुपाने जो रिपोर्ट जारी की है वह पूरी फर्जी और सत्यता से परे है।

बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई?

पेज 1 का शेष

हमने भाजपा नेताओं के भाषणों में कही गई बातों की तुलना कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखी गई बातों से की और ये समझने की कोशिश की कांग्रेस पर लग रहे आरोपों का क्या आधार है या फिर वे निराधार हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'कांग्रेस ने अपने मैनिफ़ेस्टो में जो कहा है, वो चिंताजनक है, गंभीर है. अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा. हमारी बहनों के पास सोना कितना है, उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा. हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा.' जबकि कांग्रेस घोषणापत्र में संपत्ति के पुनर्वितरण की बात नहीं है. घोषणापत्र में कहा गया है कि 'साल 2014 और 2023 के बीच अमीर और ग़रीब के बीच असमानता में खासकर वृद्धि हुई है.'

प्रधानमंत्री मोदी के आरोप के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसीलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं. वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गयी है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं. वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गयी है.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, 'इस बार के घोषणापत्र में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है, जो यदि लागू किया, तो उसमें सशस्त्र सेनाओं को भी इसके दायरे में ये ला सकता है. यह देश की एकता-अखंडता को प्रभावित करने वाला विचार है.'

जबकि राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि घोषणापत्र के किस हिस्से से उन्हें ऐसा इशारा या संकेत मिला. घोषणापत्र में 'आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण' की बात है.

साथ ही घोषणापत्र में कांग्रेस ने गारंटी दी है कि, 'वो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदायों के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पास करेगी.'

इसके अलावा घोषणापत्र का एक हिस्सा 'धार्मिक और भाषा-संबंधी अल्पसंख्यकों' को लेकर है जिसमें विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बहाल करने और स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाने की बात की है. साथ ही घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोज़गार, बिज़नेस, सर्विसेज़, खेल और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने की बात की गई है.

कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट प्रमुख पवन खेड़ा ने लिखा, 'प्रधानमंत्री को चुनौती है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा, 'जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं तो दो बातें उस घोषणापत्र में नज़र आती हैं. एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे. इसका मतलब बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग ख़तरा पैदा करना चाहते हैं. ये देश के संविधान के लिए ख़तरा पैदा करना चाहते हैं. तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं. क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे?' दूसरी तरफ़ कांग्रेस के घोषणापत्र में 'धार्मिक और भाषा-संबंधी अल्पसंख्यकों' के हिस्से के नीचे लिखा गया है, 'हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करेंगे. ऐसे सुधार समुदायों की सहमति और उनके सहयोग से ही होने चाहिए.'

घोषणापत्र में 'शरिया', 'तालिबान' जैसे शब्द नहीं हैं, इसलिए ये साफ़ नहीं कि उन्होंने ये बातें किस आधार पर कहीं.

बचत घटी और बढ़ गया कर्ज, सेविंग में तो हम 50 साल पीछे पहुंच गए, क्या कह रही है आरबीआई की रिपोर्ट!

भारत की शुद्ध बचत की दर तेजी से घटी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में देश की नेट हाउसहोल्ड सेविंग की दर में भारी कमी हुई है। एक साल पहले के मुकाबले इसमें 19 फीसदी कम हो गई है। यही नहीं, भारतीयों पर कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ा है...

ऐसा कहा जाता है कि भारत में कमाने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों की आमदनी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी कमा रहे हैं, उसे खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। बचत में काफी कमी हो गई है। स्थिति यह है कि भारत का घरलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गया है। यह कहना है हाउसहोल्ड एसेट और लायबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट का।

रिजर्व बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं

रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान नेट हाउसहोल्ड सेविंग गिर कर 5.1 फीसदी रह गई है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो इस साल भारत की शुद्ध बचत गिर कर 13.77 लाख करोड़ रुपये रह गई है। यह बीते 50 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे एक साल पहले ही यह 7.2 फीसदी थी। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोगों की आमदनी में भारी कमी आई है। साथ ही कोरोना काल के बाद लोगों के कंजप्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। लोग बचाने के बजाए खर्च ज्यादा करने लगे हैं।

बढ़ रही है देनदारी

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से एक चिंताजनक सिगनल भी मिल रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की फाइनेंशियल लायबिलिटीज तेजी से बढ़ी है। साल 2022-23 में यह तेजी से बढ़ते हुए जीडीपी के 5.8 फीसदी तक पहुंच गई। जबकि एक साल पहले यह महज 3.8 फीसदी ही थी। इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन परपस के लिए ज्यादा लोन लेने लगे हैं। चाहे वे घरेलू सामान खरीद रहे हैं या जमीन, मकान, दुकान आदि खरीद रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद यह दूसरा मौका है जबकि लोगों की फाइनेंसियल लायबिलिटीज इतनी तेजी से बढ़ी है। इससे पहले साल 2006-07 में यह दर 6.7 फीसदी थी।

घट रहा है हाउसहोल्ड एसेट

आरबीआई के मुताबिक अबसोल्यूट टर्म में देखा जाए तो साल 2020-21 के मुकाबले 2022-23 के दौरान नेट हाउसहोल्ड एसेट में भारी गिरावट हुई है। साल 2020-21 के दौरान शुद्ध घरेलू संपत्ति 22.8 लाख करोड़ रुपये की थी जो कि साल साल 2021-22 में तेजी से घटते हुए 16.96 लाख करोड़ रुपये तक गिर गई। साल 2022-23 में तो यह और घट कर 13.76 लाख करोड़ रुपये ही रह गई। इसके उलट फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करें तो हाउसहोल्ड डेट या कर्ज बढ़ोतरी ही हो रही है। साल 2021-22 में यह जीडीपी के 36.9 फीसदी थी जो कि साल 2022-23 में बढ़ कर 37.6 फीसदी तक पहुंच गई।

इसके पीछे क्या है कारण

इस रिपोर्ट पर गौर करें तो बचत घटने और कर्ज बढ़ने के पीछे बढ़ती महंगाई का बड़ा हाथ है। रिजर्व बैंक ने जो हाउसहोल्ड एसेट और लायबिलिटीज के आंकड़े जारी किए हैं, वह अर्थव्यवस्था की तत्काल विकास क्षमता **immediate growth potential** के बारे में चिंता पैदा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट कंजप्शन या निजी उपभोग से ग्रोथ को मिलने वाला समर्थन अनुमान से कमज़ोर हो सकता है, भले ही निजी पूंजीगत व्यय चक्र में देरी होती दिख रही हो।

मोदी ने लूट के लिये पौराणिक तीर्थों की पवित्रता नष्ट की

काशी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, अयोध्या में नष्ट किये हजारों मठ, मंदिर, मढ़ियें, तीर्थ क्षेत्र को कमाई के लिये पर्यटन स्थल बना, बना दिये अय्याशी मौज मस्ती और मनोरंजन के अड्डे

सनातन धर्म की रक्षा की ठेकेदार बनने वाली यथार्थ में हिंदुओं को खत्म करने वाली राक्षस सेवा संघ में हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी 1930 से ही बंटवारे का कारण बनने वाली, इसके बाद 1989 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करवाने वाला उस समय कश्मीर में पीडीपी की सरकार को भाजपा बाहर से सरकार चलाने में मदद कर रही थी और उस समय में मोदी वहां का प्रभारी था। लाखों कश्मीरी पंडितों का न केवल नरसंहार करवाया, वरण हजारों महिलाएं गायब करवाने के साथ हजारों का बलात्कार करवा कर चुपचाप देखती रही उस समय चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए उसको बदनाम किया गया। जबकि कांग्रेस ने पूरे प्रयास किया उसको रोकने के लिए जो उन्होंने हर प्रयास को नाकाम करते रहे बाद में बाबरी मस्जिद कांड में 1991 में जितने भी रामसेवक लौट रहे थे उनकी बोगियों में आग लगवा हजारों राम भक्तों को जिंदा जलवा हत्या करने वाला भी मोदी ही था। बाद में गुजरात के दंगों में भी गोधरा कांड में भी हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई गई तब भी राक्षस सेवा संघ अपने ही शाखा के सेवकों की खुली हत्या पर भी चुपचाप मौन धारण किए रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बाबा काशीनाथ कारीडोर बनाने के नंबर लगभग डेढ़ हजार छोटे बड़े मंदिर मठ मढ़िया और हजारों प्राचीन काल के साधुओं ऋषियों मुनियों की समाधियों का नामोनिशान मिटा दिया। हजारों को बेघरबार किया गया जिसने भी बोलने की कोशिश की उसको देशद्रोही कहकर उसका मुंह चुप कर दिया गया और सनातनियों की संरक्षक ठेकेदार राक्षस सेवा संघ व हमारे सनातनी ब्राह्मण बनिए राजपूत इतने बड़े संहार को देखकर भी चुपचाप रहे। यही हाल उज्जैन, अयोध्या, ओंकारेश्वर व अन्य तीर्थ स्थानों पर किया। एक तरफ बिना किसी ठोस नियोजन के 5 से 10 गुना ज्यादा की डीपीआर बनाकर हजारों करोड़ के ठेके मोदी ने अपने ही खास लोगों को दे मोटी कमाई की। तो दूसरी तरफ सभी तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता नष्ट कर सभी तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बना मौज मस्ती और मनोरंजन का कई गुना ज्यादा कीमत के लूट के अड्डे बना दिए।

ओंकारेश्वर काशी विश्वनाथ उज्जैन और अयोध्या का लाखों साल पुराना इतिहास रहा है। जहां पर सनातन शास्त्रों में वर्णित देवियों, देवताओं, ऋषियों, मुनियों, शास्त्र करोंमें तपस्या की विभिन्न विधियों पर ग्रंथ लिखे उनके मठों मंदिरों मढ़ियों समाधियों के रूप में धरा पर जो उस काल व युग के स्मरण चिन्ह स्थापित थे उन सबको तोड़फोड़ कर सदा के लिए खत्म कर दिया गया फिर भी ब्राह्मणों की महासभा के, बनियों राजपूतों चेतन गाजू के मुंह से इस बर्बादी पर आवाज नहीं निकली और जहां तक आरएसएस का सवाल था। तो वह तो पूर्ण रूप से सनातनियों को नष्ट करने में मोदी की छत्रछाया में खेल धन बटोर कर चुप बैठी है।

'बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें, तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है।' - मार्क ट्वेन

प्राचीन हिन्दू इतिहास के अनुसार काशी का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है लेकिन भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक यह शहर केवल 5,000 वर्ष ही पुराना है। 5 हजार वर्ष पुराने महाभारत से भी कई हजार साल पुराने ग्रन्थ रामायण में काशी का वर्णन आता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर काशी यानी वाराणसी को देश का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। चन्द्राकार उत्तरवाहिनी पावन गंगा के किनारे बसी विश्वनाथप्रिया काशी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जिसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने अठारहवीं शती में बनवाया था। भगवान् शिव के त्रिशूल पर बसी त्रैलोक्य-न्यारी मोक्षदायिनी काशी को शिव नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां की गलियां, मठ, मंदिर, संस्कृति, परम्परा आदि पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय है। स्कंदपुराण के काशी खण्ड में यहां के तीर्थों, घाटों का आख्यान, गंगा महिमा, वाराणसी महिमा, ज्ञानवापी माहात्म्य, त्रिलोचन आविर्भाव आदि का उल्लेख आता है। वाराणसी केवल हिन्दुओं के लिए ही खास नहीं है यहां से कुछ किलोमीटर दूर सारनाथ है, जहां गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। संस्कृत पढ़ने से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के लिए प्राचीनकाल से ही लोग वाराणसी आया करते हैं और ये क्रम आज भी जारी है। (शेष पेज 3 पर)

सभी नगरी निकायों में हजारों करोड़ के घोटाले में लीपा पोती की तैयारी

भ्रष्ट जालसाज मंत्री पार्षद आयुक्त अधिकारी इंजीनियर कर्मचारी ठेकेदार सभी फर्जीवाड़े के हिस्सेदार

राजवाड़े पर 15X15मी. के छत्रियों के सामने क्षेत्र में 40 से ज्यादा चैंबर, पूरे प्रदेश के सभी निकायों में ऐसा ही भ्रष्टाचार

प्रदेश के सभी निकायों में चुनावों से चुने जाने वाले पंचों सरपंचों पार्षद से लेकर महापौर तक आखिर लाखों, करोड़ो रुपए खर्च कर क्यों पद हथियाए जाते हैं। ताकि जनता को विभिन्न माध्यमों सुविधाओं के नाम पर लूटने के साथ-साथ सरकार से मिलने वाले धन में भी कार्य व अवसर के अनुसार मिलने वाले भ्रष्टाचार की धन के लिए ही चुनाव में धन बर्बाद किया जाता हैहाल ही में नगर निगम इंदौर में पकड़े गए नालियों पाइपलाइन को बचाने के नाम परचल रहे भ्रष्टाचार की खबरों जिन्हे लगातार मे पिछले 20 सालो से छप रहा हूं किसी ने ध्यान नहीं दिया पर अब सच सामने आ रहा है। ऐसा ही भ्रष्टाचार जलापूर्ति में पिछले 15 सालो से कुंडली मारे बैठे वर्तमान कार्यपालन यांत्रिक व प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने भी हजारों करोड़ो का पिछले 15 सालो मेंभ्रष्टाचार की है इसलिए ही वह यहां से हटना नहीं चाहता। अभी जांच कमेटी बनाने का नाटक नौटंकी के साथ पुलिस को फाइलें सौंपने के षड्यंत्र की कहानी का आगे का कच्चा चिट्ठा नीचे देख सकते हैं।

उल्टे ही जानबूझकर पुलिस को घुसेड़ा ही इसलिए गया है ताकि वह आसानी से सारी फाइल इकट्ठी करके अपने पास रख ले और यहां के घोर भ्रष्ट रंगा बिल्ला कैलाश और रमेश के दबाव के बाद सारी फाइलें गायब कर दी जाएगी और प्रकार न्यायालय में मुकदमा लगाने के बाद में पुलिस बोल देगी कि सारी फाइलें गायब हो गई है। और सब के सबभ्रष्टाचार का पैसा हजम करते हुए आसानी से पाक साफ सिद्ध हो जाएंगे जैसा की भेड़ियो का हजारों करोड़ से लेकर सिंहस्थ और सभी प्रकार के लाखों करोड़ के घोटाले में पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में और 10 सालों से देश में हो रहा है।

अंत में सब लीपा पोती कर दी जाएगी। अंत में सब बाइज्जत बरी हो जायेंगे। समय माया समाचार पत्र में मैंने लिखा है। यह सैकड़ो करोड़ का नहीं हजारों करोड़ो का घोटाला है। इसका छोटा सा उदाहरण है। बिना सही तरीके से टोपो और कान्टूर मैप को ध्यान में रख डिजाइनिंग और प्लानिंग किये। आपने देखा केवल लूटने भ्रष्टाचार करने मोटे बिल बनाने एक ही सड़क पर पिछले 10 वर्षो में ही हर वर्ष सड़कें खोदकर सीवर लाइन के पाइप डाले व चैंबर बनाए गए। वर्तमान में 5 मीटर की चौड़ी गलियों से लेकर एक ही सड़क पर हर 5-10 मीटर पर दाएं बांई तरफ में और बीच में बिना देखरेख के उल्टे सीधे कही पर बिना उचित खुदाई व जल के त्वरण वेग से बहाव को ध्यान में रख कभी 2' कभी 3' फुट कभी 4', 5', 6' से 10-15' खोदकर कभी 1' कभी 2' कभी 3' कभी 4' से 9' के पाइप डाल चैंबर ही चैंबर बना दिए गए।

उन चेम्बरों के ढक्कनों में भी पूरे इंदौर में कही लोहे की छड़ो के कही सीमेंट के खतरनाक तरीके से बना पैदल व वाहन चालकों की मौत का सामान सड़कों पर इकट्ठा कर दिया। बीच सड़क में होने के कारण कब कांटेक्ट नंबर छूट जाएगा कब कौन सा पैदल 2, 3, 4 पहिया चालक उन के खतरनाक ढक्कनों से घायल होने से अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएगा मालूम नहीं।

फिर भी 1-2 सेमी बरसात होने पर भी पानी नहीं निकलता और चारों तरफ पानी के साथ ऊबड़ खाबड़ सड़कों कीचड़ भर जाता है। जिससे जनता परेशान होती रहती है। अब यदि इन सब निर्माण की निविदाओं की सरसो बनाने वाली ठेकेदारो कंपनियों कालेखा-जोखा निकल जाए और किस पार्षद ने प्रस्ताव बनवाया कितने का वास्तविक जिस समय में निर्माण कार्य हुआ था (शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958